

LOK SABHA DEBATES

1

LOK SABHA

Friday, December 5, 1969/Agrahayana,
14, 1891 (SAKA)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Misuse of Section 107 of the Criminal Procedure Code against Political Workers

*421. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Section 107 of the Criminal Procedure Code is being used against political workers in most States, especially in areas where Judiciary has not been separated from the Executive;

(b) whether Government's attention has also been drawn to the comments of the Privileges Committee on the abuse of this Section in its report submitted to Lok Sabha on 30th August, 1969;

(c) whether Government intend to issue instructions to the State Governments advising them not to use this section for prosecuting political workers; and

(d) if not, reasons thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) Some instances had been brought to our notice where such proceedings had been instituted in respect of political workers.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). The report has been referred back to the Committee of Privileges on November 24, 1969 for reconsideration

2

after hearing Shri Madhu Limaye on the matter. The Government, however, deprecate any indiscriminate resort to proceedings under Section 107 Cr. P. C.

श्री मधु लिमये : मैं आपका ध्यान दो केसिस की ओर दिलाना चाहता हूँ। ये केसिस प्रिविलेजिज़ कमेटी की रपट आने के बाद घटित हुए हैं। इनमें नए नोटिस जारी करने का प्रयास किया गया है। मैंने यह सुना है कि मैजिस्ट्रेट इसके लिए तैयार नहीं था और उसने कहा था कि कोई शान्ति भंग का खतरा नहीं है। लेकिन कलैक्टर ने उसके ऊपर दबाव डाला। ऐसे राज्यों में जहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव नहीं हुआ है वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस तरह का दबाव डाला करते हैं। इसलिए मेरा पहला प्रश्न यह है कि बिहार में जहाँ राष्ट्रपति का शासन है तथा ऐसे राज्यों में जहाँ केन्द्र का सीधा सम्बन्ध है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव करने के लिए आप कोई कदम उठावेंगे तथा अन्य राज्यों से भी कहेंगे कि संविधान की जो धारारें हैं हालांकि उसके बारे में आप न्यायपालिका के सामने नहीं जा सकते लेकिन निर्देशक सिद्धान्त हैं, उसका पालन करवायेंगे ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I would like to give some information to the hon. Member about the separation of the judiciary from the executive. Even in some States, where the separation has taken place under legislation, these proceedings are resorted to because these preventive measures have been kept with the executive..... (Interruption).

श्री मधु लिमये : मैं अलगाव की बात कर रहा हूँ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : अलगाव करने के बाद भी ये चीजें चलती हैं। अलगाव करना ही एक मात्र रास्ता नहीं है। डिसक्रि-मिनेट यूज ही सबसे अच्छा है।

श्री मधु लिमये : मैंने यह इस वास्ते कहा है कि बिहार में इस वक्त राष्ट्रपति का शासन है। संविधान में निर्देशक सिद्धान्त है। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव किया जायगा ? जिस राज्य के मंत्री महोदय मुख्य मंत्री थे उसमें यह काम किया गया। अभी कुछ राज्यों में नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। इसलिए मेरा सवाल था कि संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों का क्या बिहार में वह पालन खुद करेंगे और अन्य राज्यों में करवायेंगे ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I think, this is a very good suggestion. I would certainly like to do it but I will have to find out the feasibility, practicability and desirability of legislation.

श्री रवि राय : कब करेंगे ?

SHRI Y. B. CHAVAN : President's rule has come after 22 years, not before that.

श्री मधु लिमये : दो उदाहरण तो मैंने ये कहे। इसी दिल्ली शहर में जिसका दायित्व अंतिम इनका है, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा को धारा 107 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और बाद में शायद बांड वगैरह लेकर छोड़ दिया गया। मेरे बारे में भी नया आदेश जारी किया गया है। मंत्री महोदय इसकी आड़ न लें कि मामला प्रिविलेजिज कमेटी में गया हुआ है। वह दूसरी बात को लेकर गया है। प्रिविलेजिज कमेटी की सिफारिशें अपनी जगह पर हैं। यह कहा जाता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल न किया जाए। आप इन्कार नहीं करेंगे कि मैं और तारकेश्वरी जी दोनों राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। मेरी बात तो आप छोड़ दें। इसलिए क्या इसके बारे में कोई ठोस निर्देश आप सब राज्य सरकारों को देंगे ?

SHRI Y. B. CHAVAN : We accept the view that no indiscriminate use of this provision should be made. I have no doubt about that :

श्री सरजू पाण्डेय : राज्य सरकारें राजनीतिक कार्यकर्ताओं को धारा 107 में बन्द करती हैं। खुद हम लोग उसका शिकार बन चुके हैं। जहाँ तक कि शान्तिपूर्ण सत्याग्रह भी जब किया जाता है तो भी इस दफा को लागू किया जाता है। क्या आप राज्य सरकारों को आदेश देंगे या उनसे बात करेंगे कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ जहाँ कोई हिंसात्मक कार्रवाई भी नहीं होती है, इस धारा का प्रयोग न किया जाय, बिल्कुल भी न किया जाए ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I cannot give any direction to State Governments; but this view certainly can be conveyed to State Governments.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Ordinarily, the processions are terminated near the India Gate. I would like to know why the procession which was organised on the 16th of last month was allowed to come just near the main gate of the Parliament House.

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not think it was on the 16th; it was on the 13th. I looked into that matter. I find, normally, Section 144 is promulgated two days before the Parliament session begins. So, it was promulgated on the 14th.

श्री क० ना० तिवारी : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि बिहार के बारे में देखेंगे ? क्या उनको यह मालूम है कि बिहार में ज्यूडिशरी और एग्जैक्टिव को अलग अलग कर दिया गया है ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I don't think so. Perhaps, partially, it has been done in some Districts.

श्री मधु लिमये : कौन डिस्ट्रिक्ट्स में ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I will require notice for that.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Is the hon. Home Minister aware of the fact that during the course of the last 18 or 19 days, there is a strike of about 40,000 engineering workers going on in Jamshedpur and that against 9 or 10 people who are described as C.P.I., P.S.P. and S.S.P. and a section of I. N. T. U. C. local leaders, charges have been framed under Section 107 although they are not involved in any kind of violence or clashes or anything of that kind ? They are being prosecuted. As Mr. Madhu Limaye said, there is the President's Rule in Bihar. The strike is peaceful. But the political workers of local parties are being harassed and prosecuted under Section 107. Will he kindly look into the matter and see that such prosecutions are not launched and the cases are withdrawn ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not know the facts. Whether it is a breach of peace or not, it is for the local officers to consider.

SHRI INDRAJIT GUPTA : I am making a complaint in all seriousness. I request you to kindly look into it.

SHRI Y. B. CHAVAN : You write to me giving all the details and I will certainly look into it.

SHRI LOBO PRABHU : Sir, Section 107 provides for taking bonds from persons who are likely to take action which may lead to a breach of peace. A breach of peace involves not only certain parties involved in an agitation but involves public too. I would like to know from the hon. Minister whether he will see, wherever there is any danger to the peace, that the magistrates and the police follow the law to the last letter.

MR. SPEAKER : Shri Kanwar Lal Gupta.

SHRI LOBO PRABHU : May I have an answer ?

MR. SPEAKER : You have advised him to follow the law. (*Interruptions*) May I ask what was the question ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not know what is the question. It is obvious. Naturally, the magistrates are supposed to discharge their duties under the Act.

MR. SPEAKER : It is a suggestion for action.

श्री कंवर लाल गुप्त : दिल्ली सीधे तौर से गृह मंत्री महोदय के नीचे है। पिछले तीन सालों में हजारों और सैकड़ों जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, स्वयं मैं भी और करीब करीब सभी जितने जन संघ के पार्लियमैंट के मੈम्बर हैं, वे भी 107 और 151 में बन्द किये जा चुके हैं उस वक्त इनको किया गया जब वे घर पर बैठे थे और इसलिए उनको बन्द किया गया कि वे जन संघ के थे। हमने कोई किसी मीटिंग में भाग नहीं लिया, कुछ काम नहीं किया लेकिन उसके बावजूद भी हमें बन्द किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग दफा 144 तोड़ते हैं, प्रधान मंत्री को बघाई देने के लिए जाते हैं, उन इलाकों से होकर जहां दफा 144 है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी है। क्या मंत्री महोदय विश्वास दिलायंगे कि इस प्रकार का जो डिसक्रिमिनेशन है नहीं किया जाएगा ? निर्जालगप्पा साहब की गाड़ी रोकी गई और वहां गड़बड़ी की गई। उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई इस बहाने से कि किसी ने रिपोर्ट नहीं की। क्या पुलिस को खुद कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिये थी ? यह डिसक्रिमिनेशन न हो, इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not think there was any discrimination. But certainly if any instances are pointed out, I will look into them.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I have already written a letter to you.

SHRI Y. B. CHAVAN : I am looking into it.

SHRI SAMAR GUHA : In view of the fact that there has been recently a number of communal troubles all over the country and also recently in West Bengal troubles were brewing during the course of harvesting of crops, would the Government apply

Sec. 107 for prevention of communal troubles and clashes during harvesting in West Bengal ?

SHRI RANGA : Not only communal but political also.

SHRI Y. B. CHAVAN : If there is any apprehension of communal or other troubles, naturally they will make use of this section.

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार में राष्ट्र-पति का शासन है। सरकार कहती है कि किसानों का जमीन पर हक होना चाहिये। बिहार में किसान या मजदूर जिस फसल को उन्होंने बोया है, उसको स्वयं काटना चाहते हैं। उनको ऐसा करने से रोकने के लिए जमींदारों और जमीन मालिकों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर दफा 107 का प्रयोग किया जा रहा है, कम्प्युनिस्टों के खिलाफ, सोशलिस्टों के खिलाफ, पी० एस० पी०, एस० एस० पी० इत्यादि के लोगों के खिलाफ। क्या सरकार के पास इस तरह की कोई खबर है? मैं जानना चाहता हूँ कि कितने कार्यकर्ताओं के खिलाफ और इस नाम पर दफा 107 का प्रयोग अभी किया गया है।

मजदूर यदि कोई आन्दोलन करते हैं तो उनके खिलाफ तो इसका प्रयोग किया जाता है लेकिन मालिकों के खिलाफ नहीं किया जाता है। मैं जानता हूँ कि बिहार काटन मिल्लज लिमिटेड फुलवारी शरीफ के मालिकों के खिलाफ इस धारा का प्रयोग किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ मालिक लोग भी हैं कारखानों के जिन पर 107 लगाई गई है बिहार के अन्दर।

SHRI Y. B. CHAVAN : We will look into it.

Filling up of posts Reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by Members of that Community

*425. SHRI JAGESHWAR YADAV
SHRI ESWARA REDDY :
SHRI P. C. ADICHAN :
SHRI C. JANARDHANAN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Services are filled up by candidates belonging to other communities on the plea that sufficient number of candidates from Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for these posts; and

(b) if so, the steps Government have taken to ensure that the posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are filled up by candidates belonging to these communities only ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) The vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Services are filled up by candidates belonging to other communities only when suitable candidates belonging to the reserved communities are not available, even though certain safeguards are provided.

(b) A statement showing the steps taken by the Government to increase the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against the reserved vacancies, is laid on the Table of the House.

Statement

Vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are dereserved and filled with general candidates only if suitable Scheduled Castes/ Scheduled Tribes candidates are not forthcoming. All the Ministries/Departments have been instructed to bring the reserved vacancies filled by direct recruitment (other than the reserved vacancies, recruitment to which is made through the U. P. S. C.) to the notice of the members of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes by :

- (1) advertisement in newspapers;
- (2) notifying to employment exchanges; and
- (3) intimating the recognised association of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Even after taking all these steps, if suitable Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates are not available, then only the appointing authorities can get the reserved